

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2312/2004/सीकर मोतीराम व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य	
	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य</p> <p>उपस्थित:- (1) श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक :</p> <p>यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर खण्डेला के निर्णय दिनांक 27-5-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- आक्षेपित आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर न्यायालय द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-1-2004 को अपास्त कर मूल वाद को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये हैं।</p> <p>3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।</p> <p>4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण पर नोटिस पूर्णतया तामील हुआ है और वे न्यायालय में हाजिर भी हुये किन्तु प्रतिवादीगण दिनांक 18-10-03 को हाजिर नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध सही तौर पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये प्रार्थीगण का वाद डिक्री कर दिया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की मंशा न समझ कर विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक भूल की है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 27-5-2004 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 15-1-04 को बहाल रखा जावे।</p> <p>5- जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण जबाब दावे में चल रहा था। जबाब दावे हेतु प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 28-11-02 नियत थी। उक्त तिथि को पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं आई। उक्त तिथि को पर्चा तारीख पेशी कायम किया गया। पत्रावली दिनांक 7-10-03 को नम्बर पर ली गई। दावे में प्रतिवादीगण के वकील को कोई सूचना नहीं दी गई। रीडर ने पत्रावली में प्रतिवादीगण के वकील की हाजरी गलत दर्ज की है। पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे वे दौरे पर थे। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित किया</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2312/2004/सीकर मोतीराम व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य	
	<p>जाना चाहिये। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में 2010आर बी जे पेज 197, 2008 आर बी जे पेज 355,539,2001आर आर डी पेज 262, 2018डी एन जे(3) पेज 313, ए आई आर 1973 एस सी पेज 76 की नजीरें पेश की।</p> <p>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।</p> <p>7- विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण जबाब दावे में चल रहा था। जबाब दावे हेतु प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 28-11-02 नियत थी। उक्त तिथि को पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं आई। उक्त तिथि को पर्चा तारीख पेशी कायम किया गया। पत्रावली दिनांक 7-10-03 को नम्बर पर ली गई। दावे में प्रतिवादीगण के वकील को कोई सूचना नहीं दी गई। रीडर ने पत्रावली में प्रतिवादीगण के वकील की हाजरी गलत दर्ज की है और पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे वे दौरे पर थे ऐसा उल्लेख आदेशिका में अंकित है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है और उनके द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.)</u></p> <p>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13- Passing of decree without service of proper notice is sufficient ground for setting aside ex-parte decree. In the absence of a notice, we do not see any justification to pass the ex-parte decree and, therefore, we are of the clear opinion that both the court below have erred in rejecting the applicatin under order IX Rule 13. In our opinion the non service of the notice was a sufficient reason to set aside the decree against the defendant no.3 (appellant herein).</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.)</u></p> <p>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13- When summons were not served to the defendant- Ex-parte decree was rightly set aside after three years. In this case, plaintiff-petitioners filed suit for declaration and permanent injunction in respect of disputed land which was decreed ex-parte against defendant. Defendants filed an</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2312/2004/सीकर मोतीराम व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य	
	<p>application for setting aside ex-parte decree on the ground that proper summons were not served on them. Trial Court dismissed the application but RAA accepted the appeal filed by defendant and set aside the ex-parte decree. The Board of Revenue maintained the order of the RAA. The Hon'ble High Court held that in the light of judgments passed by all the three courts below and after considering the same, the judgments passed by the Revenue Appellate Authority as well as Revenue Board are justified in the eyes of law.</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RRD 2001 page 262 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><u>RRD 2001 page 262</u></p> <p>Code of Civil Procedure, Order 5 rule 17 and Order 9 Rule 13 - Service of summons - No personal service was made on defendants - Process server made report that he had visited the village and defendant has refused to accept the notice and he (process server) pasted the notice on the wall - Ex-parte proceedings and ex-parte decree - Application for setting aside ex-parte decree rejected by trial court - Appeal against - Held trial court should have got the process server produced in the court for examination on oath when defendant was denying the fact that process server had ever visited the village and had made any such report and even had pasted the notice. It is bounded duty of court to see that the party is served in accordance with law before to proceed ex-parte just on receipt of report of process server - Court should see that every provision of O.5 should be completed and accomplished in letter and spirit before ex-parte proceedings are ordered. In this case there is serious doubt about service having been effected on defendant, therefore, ex-parte proceedings, set aside .</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 DNJ (SC) page 313 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p>2018 DNJ (SC) page 313</p> <p>Civil Procedure Code, 1908 -O.5, R.20; O.9, R. 12, Sec. 27- Setting aside of ex-parte decree- Application rejected by the Trial Court- Summon served publishing in newspaper- No specific day, date and time given in summons for appearance- Non-compliance of mandatory statutory requirement- No proper service of summons- Held, ex-parte decree is set aside and the trial court is directed to decide the suit on merits.</p> <p>उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2312/2004/सीकर मोतीराम व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य	
	<p>की जाती है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20-8-2018को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम छ माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।</p> <p>निगरानी के साथ मूल दावा संख्या 830/2002 की पत्रावली संलग्न है। आदेश 9 नियम 13 की पत्रावली संलग्न नहीं है। सहायक कलेक्टर के पत्र में यह नोट अंकित है कि आदेश 9 नियम 13 की पत्रावली पहले भेजी जा चुकी है। मूल पत्रावली भेजी जा रही है। इसलिये पत्रावली तलाश कर निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी की पत्रावली जो पूर्व में मण्डल को प्रेषित की जा चुकी है, उक्त पत्रावली निगरानी के साथ क्यों संलग्न नहीं की गई इस बाबत सम्बन्धित अहलमद से स्पष्टीकरण लिया जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(धूकलराम कसवाँ) सदस्य</p>	